Publication	**Hari Bhoomi**	**Language**	Hindi
Edition	New Delhi	**Journalist**	Shambhu Bhadra
Date	30/06/2025	**Page no**	8
CCM	125.40		

The problems of the cooperative sector should be resolved

सहकारिता क्षेत्र की दिक्कतें हों दूर

आर्थिकी

शंभू भद्रा

सहकारिता मंत्री के तौर पर अमित शाह ने सोये हुए कॉपरेटिव सेक्टर को न केवल जगाया है, बल्कि नई नीतियों व कार्यक्रमों से इसमें ऊर्जा का संचार भी किया है। आज देश में सहकारिता 'सहकार से समृद्धि' के मोटो के साथ एक आर्थिक बदलाव और गरीबी उन्मूलन का केंद्रीय अस्त्र बन चुकी है। देश में करीब 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सहकारी योजनाओं ने भी अहम भूमिका निभाई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया। साफ है कि दुनिया सहकारी अर्थशास्त्र की ओर तेजी से बढ़ रही है। भारत के पास इस क्षेत्र में प्रगति के लिए पारिस्थितिकी भी है और प्रगाढ़ आवश्यकता भी।

आज केंद्र सरकार सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए मंथन बैठक कर रही है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह देश में सहकारिता के विकास में खास रुचि ले रहे हैं। सहकारिता मंत्री के तौर पर अमित शाह ने सोये हुए कॉपरेटिव सेक्टर को न केवल जगाया है, बल्कि नई नीतियों व कार्यक्रमों से इसमें ऊर्जा का संचार भी किया है। आज देश में सहकारिता 'सहकार से समृद्धि' के मोटो के साथ एक आर्थिक बदलाव और गरीबी उन्मूलन का केंद्रीय अस्त्र बन चुकी है। देश में करीब 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में कॉपरेटिव योजनाओं ने भी अहम भूमिका निभाई है।

जब मौजूदा विश्व में पूंजीवादी अर्थवाद और कॉपोरेट पूंजीवाद उम्मीदें नहीं जगा रहे हैं, उल्टे ये आर्थिक असमानता की खाई बढ़ा रहे हैं व आर्थिक क्रांति के तौर पर पेश किए गए साम्यवाद नब्बे के दशक में ही दम तोड़ चुका है और सही मायने में इस वक्त दुनिया नव आर्थिक वैचारिकी (नए आर्थिक मॉडल) के संकट के दौर से गुजर रही है, तब कॉपरेटिव इकोनॉमिक सिस्टम (सहकारी आर्थिक तंत्र) उम्मीद जगाता है। आर्थिक स्वतंत्रता, समावेशी विकास, गरीबी उन्मूलन, आर्थिक लोकतंत्र, आर्थिक असमानता के गैप को भरने के भागीरथ लक्ष्यों को सहकारी आर्थिक तंत्र के कुशल क्रियान्वयन से हासिल किया जा सकता है। भारत ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति भी की है, लेकिन अभी भी भारत की आर्थिक नीति व विकास मॉडल में कॉपरेटिव इकोनॉमिक सिस्टम को केंद्रीय स्थान नहीं मिला है। यूं तो भारत की प्राचीनता और संस्कृति में सहकारिता के बीज हैं। वैदिक काल से स्वतंत्रता एक सहकारिता अनेक सामाजिक व आर्थिक बदलाव की शनैः शनैः साधन बनी है। आजादी के बाद इसे सरकार ने नीतिगत तौर पर गति दी। देश में आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण करने तथा सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करते हुए आर्थिक विकास में लोक भागीदारी को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया, पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता को शामिल किया गया। वर्ष 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) और वर्ष 1982 में नाबार्ड बना। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मूल अधिकार (अनुच्छेद 19) के रूप में स्थापित किया गया। हालांकि कांग्रेस नीत सरकारों की लचर नीतियों, लाल फीताशाही और संस्थागत भ्रष्टाचार के चलते सहकारिता क्षेत्र को वैसी मजबूती नहीं मिली, जिसकी जरूरत थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने सहकारिता के आर्थिक क्रांति सामर्थ्य को पहचाना और वर्ष 2021 में अलग से सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। अमित शाह जैसे फोकस्ड और दूरदर्शी विजन वाले नेता को इस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। नीतिगत तौर पर मोदी सरकार ने सहकारिता क्षेत्र का कायाकल्प किया है, शाह के मंत्रित्व में अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) अधिनियम 2023 लाया गया। कृषि, बागवानी, डेयरी, मत्स्य पालन, अनाज भंडारण, सस्ती दवा विपणन, सुलभ ऋण वितरण, सौर पंप, और ब्रिकी केंद्र जैसे क्षेत्र में सहकारिता कार्यक्रम क्रियान्वित हो रहे हैं। भारत ने गत नवंबर में अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) वैश्विक सम्मेलन की

मेजबानी की है। इसके बावजूद सहकारिता क्षेत्र अनेक चुनौतियों से गुजर रहा है, जिन्हें एड्रेस करने की जरूरत है। उम्मीद है कि इस मंथन बैठक में चुनौतियों को हल करने की दिशा में पहल हो। सहकारिता आंदोलन देश की समावेशी विकास रणनीति का आधार है। वित्तीय समावेशन, सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के माध्यम से सहकारी समितियों ने असमानताओं को कम करने एवं स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सहकारी समितियां पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं की कमी की चुनौतियों से जूझती हैं। कई सहकारी समितियों की वित्तीय संसाधनों तक पहुंच नहीं है। उनके पास वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपेक्षित औपचारिक दस्तावेज का अभाव होता है, जिससे ऋण प्राप्त करना कठिन हो जाता है। सहकारी समितियों को अक्सर समावेशिता की कमी, संरचनात्मक असमानताओं के अस्तित्व आदि से संबंधित मुद्दों का सामना करना पड़ता है। अवसंरचना संबंधी बाधाएं और कनेक्टिविटी की कमी उनकी दक्षता और प्रभावशीलता को प्रभावित करती है, जिससे पहुंच सीमित हो जाती है। तकनीकी और प्रबंधकीय प्रशिक्षण और कौशल विकास पहलों का अभाव एक और चुनौती है, जो मानव संसाधनों को पंगु बना देती है। सहकारी समितियों के कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप उनकी स्वायत्तता को कमजोर करता है और सदस्यों के हितों को प्रभावी ढंग से पूरा करने की उनकी क्षमता को प्रभावित करता है। मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने और सहकारी उत्पादों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए गोदामों, शीत भंडारण सुविधाओं और प्रसंस्करण इकाइयों जैसे बुनियादी ढांचे के विकास में अधिक निवेश की आवश्यकता है। सहकारिता की धारणा को नव प्रयोग और नवप्रवर्तन के केंद्र के रूप में परिवर्तित करना जरूरी है। सहकारी नेतृत्व वाली पर्यटन पहल होनी चाहिए। यह नया क्षेत्र होगा। वित्तीय सहकारी समितियां संसाधनों, विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए क्रेडिट यूनियनों सहित अन्य सहकारी समितियों के साथ सहयोग कर सकती हैं। इससे कार्यकुशलता में सुधार और लागत कम करने में मदद मिल सकती है।

वित्तीय सहकारी समितियां पारंपरिक बचत और ऋण से आगे बढ़कर निवेश उत्पादों, बीमा और वित्तीय शिक्षा को शामिल करने के लिए अपनी सेवाओं का विस्तार कर सकती हैं। सहकारिता को केंद्रीय आर्थिक मॉडल के घटक रूप में अपनाया जाना चाहिए। दरअसल, सहकारी अर्थशास्त्र 1700 के दशक के अंत और 1800 के दशक की शुरुआत में औद्योगिक पूंजीवाद के सिद्धांत के साथ स्टेट सोशलिज्म के रूप में विकसित हुआ। सहकारिता समाजवाद की स्थापना का ही मार्ग है। सहकारी अर्थशास्त्र आवास, भोजन, रोजगार और गरीबी की समस्याओं को हल करने में सक्षम है, जो आधुनिक पूंजीवादी व औद्योगिक व्यवस्था अब तक हल करने में असमर्थ हैं। 2012 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया था, जिसमें सामाजिक-आर्थिक विकास में सहकारी समितियों के योगदान पर प्रकाश डाला गया। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला एलिनोर ओस्ट्रोम ने सहकारी उद्यमों और संगठनों की प्रबंधन की क्षमता को राजनीतिक या बाजार के साधनों से कहीं अधिक प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया। वैश्विक मानवता का 12 फीसदी हिस्सा किसी न किसी सहकारी समिति का सदस्य है। फरवरी 2024 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया। साफ है कि दुनिया सहकारी अर्थशास्त्र की ओर तेजी से बढ़ रही है। भारत के पास इस क्षेत्र में प्रगति करने के लिए पारिस्थितिकी भी है और आवश्यकता भी।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार व आर्थिक जानकार हैं। ये उनके अपने विचार हैं।)
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

****

Downloaded from
SAMVAD